आरक्षण में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

6:1 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दे दी, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को व्यापक सुरक्षा मिल गई।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय **पंजाब अधिनियम की धारा 4(5) की संवैधानिक वैधता की समीक्षा** कर रहा था, जो इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसूचित जातियों या जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण किया जा सकता है या उन्हें समरूप समूहों के रूप में माना जाना चाहिए।

समाचार पर अधिक जानकारी

- भारत के मुख्य **न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया** कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है।
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने छह अलग-अलग फैसले सुनाए।
- **यह निर्णय ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के निर्णय को खारिज करता है,** जिसमें पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह तर्क देते हुए कहा था कि उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एससी/एसटी एक समरूप वर्ग हैं।

राज्य सरकारों के लिए नए दिशानिर्देश

- राज्य अनुसूचित जातियों के भीतर किसी एक उप-जाति को **100% आरक्षण** आवंटित नहीं कर सकते।
- राज्यों को प्रतिनिधित्व के अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण करना चाहिए।

निर्णय के पीछे तर्क

- एससी/एसटी आरक्षण के लाभों पर कुछ उपजातियों द्वारा एकाधिकार किए जाने की शिकायतों को संबोधित करते हुए, अन्य को वंचित रखा गया।
- न्यायालय का उद्देश्य सभी उपजातियों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है

प्रभाव:

- राज्य अब अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उपश्रेणियां प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हाशिए पर पड़ी उपजातियों को भी लाभ मिले।

पीजी सुविधा के दिशानिर्देश

उत्तर प्रदेश में निजी पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधाओं और छात्रावासों के संचालन के लिए जल्द ही सरकारी दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- **समिति का गठन:** दिशा-निर्देशों का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है और इसकी जांच के लिए विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, शिपू गिरि की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है।
- समिति एक माह के भीतर छात्र एवं जनता के हित में ऐसे छात्रावासों के पंजीकरण एवं संचालन के संबंध में अपनी अनुशंसा प्रदान करेगी, जिसके बाद नियम लागू किये जायेंगे।

- **सदस्यों**: समिति में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं गृह विभाग से एक-एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

लाभ:

- प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ सहित अपने गृहनगर से दूर यूपी के विभिन्न शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजी सुविधाओं और छात्रावासों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम बनाने वाले राज्य सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा लाभार्थी होंगे।
- इसके लागू होने से मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों को इन सुविधाओं में रहने के दौरान सरकारी मानदंडों के अनुसार कम से कम न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा मिल सकेगी।

मॉडल सोलर सिटी-अयोध्या

हाल ही में, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके कारण **अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त हुआ।**
- नीति के अनुसार, सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सकते हैं।
- अयोध्या ने इस बेंचमार्क को पार कर लिया है, और आवश्यक क्षमता से दोगुनी क्षमता हासिल कर ली है।

वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल (डब्ल्यूसीसी) द्वारा 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी' की उपाधि से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह मान्यता शहर की **समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत** और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल का प्रमाण है।
- कश्मीर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर प्रमाणपत्र से सम्मानित होने वाला **चौथा भारतीय शह**र बन गया है, अन्य शहर हैं:
  - राजस्थान में जयपुर
  - तमिलनाडु में मामल्लपुरम और
  - कर्नाटक में मैसूर।

लघु समाचार

- पहली बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण झूंसी में समुद्र कूप के पास 2000 तंबुओं का शहर स्थापित कर रहा है, जिससे मेहमानों को नागा साधुओं, मंडलेश्वरों और महामंडलेश्वरों की गतिविधियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके शिविर अखाड़ों के तंबुओं के करीब स्थित हैं।

- इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो (आईएचई 2024) का **सातवां संस्करण 3 से 6 अगस्त 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर** में आयोजित किया जाएगा।

अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण समसामयिकी

ओडिशा	❖ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (यूएन ईसीओएसओसी) द्वारा प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री दर्जा दिया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। विश्व भर से प्राप्त 476 आवेदनों में से केवल 19 संगठनों को, जिनमें KIIT DU भी शामिल है, इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया।

विविध

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने **टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा** का अनावरण किया, जिसमें गांधीजी की वैश्विक विरासत और शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला गया।

❍❍❍❍